B.A. II Hons Paper - IV

WORLD HISTORY

आर्थिक संकट

नई व्यवस्था

1929-32 का युग विश्व अर्थव्यवस्था के लिए अपकर्ष का युग था। विश्वव्यापी
आर्थिक मन्दी ने सारे राष्ट्रों की आर्थिक सम्भावनाओ को ध्वस्त कर डाला था।
मन्दी की इस वर्त्तुल गति का केन्द्र मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका था। वहाँ के
चालू राष्ट्रीय उत्पाद में 46% रोजगार में 20% तथा टिकाऊ वस्तुओ के उत्पादन
में 80% की गिरावट आ चुकी थी। सार में समग्र रूप में सारी अर्थव्यवस्था ही
छिन्न-भिन्न हो चुकी थी। इसी परिप्रेक्ष्य में वहाँ राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ
और डेमोक्रेटिक दल के रूजवेल्ट निर्वाचित घोषित हुए। अपने चुनाव-अभियान में
ही उन्होंने आर्थिक परिदृश्यों को प्राथमिकता दी थी; अतः इसके उपरान्त राष्ट्रीय
संकटकालीन स्थिति के लिए रूजवेल्ट ने कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया
जो अमेरीकी इतिहास में 'सौ दिन' (3 मार्च-15जून 1933) के नाम से
जाना जाता है। इन सौ दिनों के कौंग्रेस के इस अधिवेशन में देश के वित्तीय,
आर्थिक और सामाजिक जीवन के कार्यकलापों के लिए कई आवश्यक विधेयक
स्वीकृत किए गए। इस सम्बन्ध में पारित विधेयकों को दो वर्गों में विभाजित
किया जा सकता है। प्रथम तात्कालिक और आवश्यक समस्याओ से सम्बन्धित
तथा द्वितीय, स्थायी उन्नति से सम्बन्धित। इन दोनों प्रकार के विधेयकों को
क्रमशः सहायता और पुनरुत्थान तथा सुधार एवं पुनर्निर्माण की संज्ञा दी गई तथा
इन्हें ही सामूहिक रूप से न्यू डील या नई व्यवस्था का नाम दिया गया। यह नई
व्यवस्था नई सामाजिक एवं आर्थिक पद्धति या नया सन्देश के नाम से भी जानी
जाती है। वैसे रूजवेल्ट ने चुनाव प्रचार के दौरान वचन दिया था कि - "मैं देश
को एक नया व्यवहार दूँगा" अतः इसलिए यह संज्ञा अधिक लोकप्रिय है।
वस्तुतः यह एक चतुर्मुखी योजना थी, जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय जीवनोत्थान के
सभी पहलू निहित थे।

उद्देश्य :- मुख्य उद्देश्य एक अधिक टिकाऊ समृद्धि की स्थापना। इसके लिए
राजकीय नियंत्रण और हस्तक्षेप में वृद्धि करके आर्थिक मन्दी के दुष्परिणामों को
मिटाना था। पर इस राजकीय नियन्त्रण का उद्देश्य समाजवादी उपायों को लागू
करना नही था, क्योंकि उत्पादन के साधनों, वितरण और लाभ के निजी
स्वामित्व में अमेरिकियों का दृढ़ विश्वास था। वस्तुतः रूजवेल्ट अपनी अर्थव्यवस्था
द्वारा कृषि और उद्योगों में संतुलन लाना चाहते थे या मजदूरों, रोजगार देने
वालों तथा उपभोक्ताओ के बीच सन्तुलन कायम करना चाहते थे। इसका उद्देश्य
या संविधान के अन्तर्गत सभी हितों का सन्तुलन तथा सम्पत्ति, मानव समाज
और स्वधीनता को सुरक्षित रखना था। नये कार्यक्रम का दर्शन प्रजातान्त्रिक था
और इसका व्यावहारिक रूप विकासवादी था।

नीति :-

* औद्योगिक नीति
* कृषि सम्बन्धी नीति
* सामाजिक-आर्थिक पुनरुत्थान की नीति
* मुद्रा एवं साख नीति
* परिवहन नीति

Scanned by TapScanner

इस नवीन अर्थनीति का संक्षिप्त रूप [R^3]
Relief उन्मुक्ति,
Recovery पुनरुत्थान, और
Reform सुधार।

औद्योगिक नीति : 1933 में NITA (National Industrial Recovery Act) लाया गया जिसका उद्देश्य व्यापार और उत्पादन का नियमन, मजदूरी में वृद्धि, काम के घण्टों में कमी, तथा मूल्य में वृद्धि।
इसे कार्य रूप देने के लिए -NRA (National Recovery Administration) की स्थापना की गई। इसके विशेषज्ञ प्रतिनिधि उचित संहिताएँ (Fair Codes)बनाते थे। 500 प्रकार की Codes पर अन्ततः इससे छोटे वर्ग के व्यवसायियों में असन्तोष, 1935 में यह अवैध घोषित NIRA 1935 'वैगनर एक्ट' (Wagner Act) पारित। इसके द्वारा राष्ट्रीय परिषद की स्थापना। 1938 Fair Labour Standards Act न्यूनतम मजदूरी तथा काम के घण्टे निश्चित करने के लिए।
कृषि सम्बन्धी नीतिः
इस कार्यक्रम के तीन प्रमुख उद्देश्य -
किसानों की क्रय शक्ति तथा सामान्य आर्थिक स्थिति को युद्ध के पूर्व स्तर तक ले जाना।
ग्रामीण कर्ज में कमी तथा मूल्य में अतिशय वृद्धि के विरुद्ध किसानों को सुरक्षा प्रदान करना।
किसानो के फार्मों को गिरवी रखने के दबाव को कम करना।
क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए 1933 - कृषि समायोजन कार्यक्रम (Agriculture Adjustment Act), प्रारंभ में कपास, गेंहू, तम्बाकू पर।
1933 - कृषि साख विधेयक (Farm Credit Act)
आर्थिक सहायता के लिए 1933- Emergency Farm Mortgage Act (ऋण निवारण)
मकान गिरवी के लिए - 1933 Home Owners Loan Act
इस नीति का सन्तोषजनक परिणाम - आय में 59% की वृद्धि (किसानों)

सामाजिक आर्थिक पुनरुत्थान नीति :-
(a) सामाजिक सुरक्षा :- सबसे क्रान्तिकारी योजना, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम द्वारा, पूरे अधिवेशन में केवल यही विधेयक पारित किया जाता तो भी यह इस युग का ऐतिहासिक अधिवेशन माना जाता। संघीय सरकार ने राज्य सरकारों को प्रत्यक्ष अनुदान देने की घोषणा की (प्रसूति और बाल कल्याण के लिए, अन्धों के लिए प्रावधान, अपंग एवं अपाहिज के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के लिए, बुढ़ापे की बीमा योजना भी।
(b) बेराजगारीः 1933 में 1 करोड़ 40 लाख बेराजगार
1933 - Unemployment Relief Act कार्य मिले, आवास सुविधा, वस्त्र, चिकित्सा सुविधा।
1933 National Employemnt Service Act (Employment Exchange) की स्थापना

(E&H, Hon, 3/5)

(c) आवास : 'संघीय आवास प्रशासन' की स्थापना
1937 संयुक्त राष्ट्र आवास प्राधिकरण की स्थापना
(d) टेनेसी घाटी योजना: TUP इसके लिए टेनेसी वैली डेवलपमेन्ट एक्ट आया।
बहुउद्देश्यीय योजना स्थायी देन, सात राज्य शामिल, (20 लाख जनता)।

मुद्रा एवं साख नीति : तीन उद्देश्य
स्फीति नियंत्रण
बैंकिंग व्यवस्था में सुधार
प्रतिभूतियों तथा बाजारों का निरीक्षण

1933 Emergency Banking Act
1933 Farm Relief & Inflation Act
1933 Home Owners Loan Act
राष्ट्रपति को। अधिकार कि वह साख, मुद्रा और लेन देन को नियंत्रित कर सके।
1933 Banking Act इसके तहत Recontruction Finance Corporation तथा Federal Reserve Bank की स्थापना।
1935 Banking Act।
1933 Security Act।
1935 Security Exchange Act।
1936 Commodity Exchange Act।
इसके अलावा न्यूडील नीति के अन्तर्गत स्वर्णमान का परित्याग कर दिया गया तथा आयात को घटाने एवं निर्यात को बढ़ाने के लिए डालर के अवमूल्यन की नीति अपनाई गई।
कुल मिलाकर इसं आर्थिक संक्रान्ति का मुख्य कारण था- अत्याधिक बचत और कम व्यय। अतः स्थिति को समाप्त करने के लिए उपभोक्ताओ की आय बढ़ायी गई और जनता की क्रयशक्ति बढ़ाने का प्रयास करने लगी और व्यापार प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज की दर नीची रखने की नीति अपनाई गई।
मुल्यांकन : मुख्य विवाद को दो बिन्दु-
1. परोक्ष रूप से यह नीति समाजवाद की समर्थक, तथा
2. न्यूडील सफल नहीं बल्कि असफल।

पहला बिन्दु: न्यू डील के अन्तर्गत पहली बार मन्दी को दूर करने के लिए संघ सरकार द्वारा सक्रिय कदम उठाये गए। इससे पूर्व संघीय सरकार सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करके सन्तुष्ट हो जाया करती थी। अब यह बात स्वीकार की जाने लगी कि अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण आवश्यक है। न्यूडील में इस प्रकार नियंत्रण भी है और इसी पर इस राजकीय नियंत्रण को देख कुछ इतिहासकारों ने आरोप लगाया कि यह पूँजीवाद को बढ़ावा नही दे रहा है बल्कि साम्यवाद या समाजवाद के साथ समझौता कर रहा है।
पर यह भ्रामक है। इस राजकीय नियंत्रण का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि USA पूंजीवादी नीति को त्याग कर समाजवाद का समर्थन कर रहा है। फाकनर ने अपनी पुस्तक American Economic History में लिखा है कि "न्यु डील अबंध नीति (Laissez Faire) का पतन प्रदर्शित करता

Scanned by TapScanner

(E&W, Wor, 4/5)

है, किन्तु पूंजीवाद की समाप्ति नहीं।" आर्थिक दुष्परिणामों को मिटाने के लिए राजकीय नियन्त्रण में वृद्धि का उद्देश्य समाजवादी उपायों को लागू करना नहीं था क्योंकि उत्पादन के साधनों, वितरण तथा लाभ के निजी स्वामित्व में अमेरिकियों का दृढ़ विश्वास था। रूजवेल्ट ने खुद कहा था- "हम अपनी अर्थव्यवस्था द्वारा कृषि और उद्योगों में संतुलन लाना चाहते थें, मजदूर, रोजगार देने वाले तथा उपभोक्ता के बीच संतुलन चाहते हैं। साथ-साथ हमारा यह भी उद्देश्य है कि अन्तरिक बाजार समृद्ध और विशाल बना रहे और अन्य देशों के साथ हमारा व्यापार बढ़े।" अतः आर्थिक संगठनों पर सीमित नियंत्रण समाजवाद की तरफ अग्रसर होने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि पूंजीवाद को ही और सशक्त बनाने का उपकरण है।

मूल्यांकनः सफल या असफलः 'न्यू डील' के मूल्यांकन पर अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ एकमत नहीं हैं। इसके समर्थकों का कहना है कि इस नीति ने अमेरिका को आर्थिक संकट से बचा लिया। इसके फलस्वरूप रोजगार बढ़ा, कृषिगत आय तथा औद्योगिक क्रियाओं में वृद्धि हुई, व्यापार व्यवसाय बढ़े तथा बैंकिग और मुद्रा पद्धति पर लोगों का पुनर्विश्वास हुआ।

किन्तु न्यू डील के एक दूसरे पक्ष को भी कुछ आलोचक लेकर आते हैं। आलोचकों का कहना है कि अमेरिका की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाने का श्रेय न्यू डील को इतना नहीं है जितना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुधरती दशाओं को है। आलोचकों ने तो यहाँ तक कहा कि वास्तव में न्यूडील अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहा। पूर्ण रोजगार और उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके तथा आर्थिक सहायता भी धीमी और कम रही। इस नीति से किसानों को भी लाभ नहीं हुआ। फिर जो भी परिवर्तन हुए वे सरकारी व्यय के फलस्वरूप हुए। अतः 1939 में जब सरकार ने व्यय कम कर दिया तो पुनः स्थिति बिगड़ने लगी। इसके अलावा न्यू डील आर्थिक स्थिति में स्थायित्व नहीं ला सका। एक आलोचक ने तो यहाँ तक कहा कि- "रूजवेल्ट मौलिक दोषों को दूर करने में मुख्यत विफल रहें तथा उनका कार्य एक भयानक रोग के केवल लक्षणों की ही व्यावस्था करने तक सीमित रहा।" नेव्हिन्स एवं कोमेगर ने नयी नीति के क्रान्तिकारी स्वरूप को मान्यता नहीं दी तथा इसे "पुराने पत्रों की ही नई बाँट" बताया। आर्थर श्लेसेंजर ने अपनी पुस्तक 'दि एज ऑफ रूजवेल्ट' में लिखा कि यह नीति अमेरिका के उदारवादी इतिहास की ही निरन्तरता थी। इस अर्थनीति की उत्पत्ति का एकमात्र कारण आर्थिक मन्दी ही नहीं था बल्कि अगर यह मन्दी न भी आई होती तो यह किसी न किसी तरह निर्मित होती। फ्रीडेल ने इस नवनीति को उन व्यक्तियों का कार्य बताया जो प्रगतिशील युग में प्रौढ़ता और नैतिक मूल्यों से प्रभावित हो चुके थे।

इन विवादों के जाल से हटकर अगर हम नई व्यवस्था की पृष्ठभूमि तथा रूजवेल्ट के पहले के राष्ट्रपति हूबर की असफलता और कार्य न करने की मानसिकता पर दृष्टि डालें तो यह नई व्यवस्था उस युग के लिए वास्तव में नई दिखाई पड़ेंगी। प्रथम विश्वयुद्ध की चपेट उबरे विश्व तथा आर्थिक मन्दी के चक्र में पिसे अमेरिका को तत्काल इस नवनीति ने जरूर उबारा। इस न्यूडील के अन्तर्गत बनी दूरगामी योजनाओं ने तात्कालिक रूप से आवश्यक जनकल्याणकारी और उपयोगी सिद्ध हुई। और फिर जैसे-जैसे परिस्थितियाँ बदलती गई और नई आवश्यकताएँ एवं समस्याएँ सामने आती गई, उनको सुधारने के लिए योजनाओं की रूपरेखा में भी परिवर्तन होता गया। किन्तु ध्येय निरन्तर एक रहा और वह

Scanned by TapScanner

था शोषित वर्ग का उत्थान, राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य का उत्थान। और इसमें राष्ट्रपति को आशाजनक ही नहीं बल्कि उससे भी अधिक सफलता प्राप्त हुई। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अतीत में हुई घटनाओं से नई बातें सीखी; उसे परख और भविष्य निर्माण के लिए वर्त्तमान को संशोधित किया। अब समग्र रूप से भविष्य का चेहरा तो वर्त्तमान के आईने में प्रतिबिम्बित नहीं हो सकता है। संक्षेप में रूजवेल्ट की इस नीति ने आर्थिक मंदी के कुप्रभावों को बड़ी सीमा तक दूर किया और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को एक नई राह दिखलाई। इसीलिए इन वाद-विवादों के बावजुद नई व्यवस्था आर्थिक इतिहास के पन्नों में अभी तक सुरक्षित है।

Scanned by TapScanner